करेंट अफेयर्स राजस्थान

फरवरी

(संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का शुभारंभ 3
- डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 3
- एनसीसी राजस्थान ने फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में प्राप्त किया प्रथम स्थान 4
- चिकित्सा मंत्री ने किया ऑक्सीजन प्लांट व क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ 4
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च 4
- जयपुर के चौंप में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5
- राजस्थान युवा पखवाड़ा 5
- लोकायुक्त ने राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रस्तुत किया 33वाँ समेकित प्रतिवेदन 6
- गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ 6
- प्रदेश के 1001 गाँवों में सभी परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सौगात 7
- 25 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिये एमओयू 7
- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू 8
- प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता संवर्द्धन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में एमओयू 9
- रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति 9
- सघन मिषन इंद्रधनुष 4.0 अभियान 10
- 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन 10
- हल्दीघाटी युद्ध 11
- मरु महोत्सव 2022 का शुभारंभ 12
- जोधपुर के शुभम राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल 12
- सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण 13
- राजस्थान के 6 बुनकर 'बुनकर पुरस्कार' के लिये चयनित 13
- बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये रणनीति पत्र राज्य सरकार से स्वीकृत 14
- आरपीएससी एवं विभिन्न बोर्ड के अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण किया 14
- प्रदेश के कारागृहों में कॉनफैड द्वारा 'बंदी कैंटीन'की होगी शुरुआत 15
- मुख्यमंत्री ने किया 'राजस्थान स्वायत्त शासन'पत्रिका का विमोचन 15
- एनएचएम और विश फाउंडेशन के बीच एमओयू 16
- 'ऑपरेशन अस्मिता' 16
- 'मेड इन इंडिया' पुस्तक 17
- विधानसभा का आईओएस मोबाइल ऐप लॉन्च 17
- राजस्थान बजट वर्ष 2022-23 18
- राज्य बजट 2022-23 में पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा 18
- 'उदय खेल महोत्सव' का समापन 19

नोट :

राजस्थान

डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 31 जनवरी, 2022 को राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान ने इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी-होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से प्रारंभिक रूप से राज्य की कक्षा 6 से 10 तक के विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम सरल तरीके से हिन्दी व इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होगा।

प्रमुख बिंदु

- इस पॉडकास्ट कार्यक्रम से दूरदराज, आदिवासी क्षेत्रों व पश्चिमी राजस्थान के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा एवं यह पॉडकास्ट उन विद्यार्थियों के लिये भी उपयोगी साबित होंगे, जिनके पास इंटरनेट की बैंडविथ भी अधिक उपलब्ध नहीं है।
- यह पॉडकास्ट सभी विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क उपलब्ध होंगे तथा सभी पॉडकास्ट को विभाग के सोशल मीडिया पर यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा, विभाग द्वारा प्रदत्त लिंक के माध्यम से विद्यार्थी न केवल संपूर्ण विज्ञान का पाठ्यक्रम पॉडकास्ट पर सुन पाएंगे बल्कि प्रश्न-उत्तर भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021-22 में विज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिये राज्य के साइंस स्ट्रीम वाले 1700 से अधिक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस-स्पेस क्लब स्थापित करने की घोषणा की गई है।
- विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि पूर्व में जिस प्रकार रेडियो के माध्यम से समाचार, साइंस क्विज आदि कार्यक्रमों का प्रसारण होता था, उसी तरह से आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप का उपयोग करते हुए विभाग ने अपनी पहुँच अधिक-से-अधिक बच्चों में बनाने के लिये इस डीएसटी.-होम स्कूलिंग पॉडकास्ट की शुरुआत की है।
- इस कार्यक्रम से वे सभी बच्चे लाभान्वित होंगे, जो कि स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं अथवा किन्हीं कारणों से स्कूली शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बनाए गए कक्षा 6 से 10 तक के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को बिना किताबों के सिर्फ सुनकर ही समझा जा सकता है। अत: यह बच्चों के लिये ज्ञानार्जन का एक अच्छा माध्यम साबित होंगे।

डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- 2 फरवरी, 2022 को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला प्रतिष्ठित 'डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार' जयपुर के लोककला मर्मज्ञ विजय वर्मा को स्वास्थ्य कारणों से उनके निवास स्थान पर प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के राज्यपाल एवं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कलराज मिश्र के निर्देशानुसार राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने मानसरोवर स्थित विजय वर्मा के निवास पर पहुँचकर उन्हें सम्मानित किया।
- पुरस्कारस्वरूप विजय वर्मा को शॉल, प्रशस्ति-पत्र, एक लाख पच्चीस हजार पाँच सौ रुपए का चेक प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान के जाने-माने कला मर्मज्ञ पँभूषण डॉ. कोमल कोठारी की स्मृति में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर द्वारा दिया जाने वाला 'डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार' हेतु इस बार संयुत्त रूप से महाराष्ट्र के ठाणे के कला मनीषी डॉ. प्रकाश सहदेव खांडगे तथा जयपुर के विजय वर्मा को चुना गया था।

नोट :

- गौरतलब है कि डॉ. कोमल कोठारी को 'कोमल दा' के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लोक कलाओं के संरक्षण के लिये अहम कार्य किये। इन्होंने राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत और वाद्यों के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज आदि के लिये बोरूंदा में रूपायन संस्था की स्थापना की थी।

एनसीसी राजस्थान ने फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में प्राप्त किया प्रथम स्थान

चर्चा में क्यों?

- 4 फरवरी, 2022 को राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन भवन में कर्नल जितेंद्र कुमार (एस.सी.) निदेशक, नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और कर्नल संजय गुप्ता, कंटिंजेंट कमांडर, एनसीसी ने स्मृति चिह्न और एनसीसी कैप प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान एनसीसी निदेशालय के 57 एनसीसी कैडेट्स ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड शिविर में 17 दिसंबर, 2021 से 29 जनवरी, 2022 तक भाग लिया था।
- आरडीसी कैंप में राजस्थान के कैडेट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। कैंप में लाईन एरिया प्रतियोगिता, फ्लैग एरिया प्रतियोगिता, ड्रिल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गईं।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिये पर्यटन विभाग ने राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत की जानकारी प्रदान करके एनसीसी कैडेट्स की मदद की थी। नतीजतन, कैडेट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, सांस्कृतिक प्रतियोगिता में चौथा स्थान तथा समग्र रूप से आरडीसी 2022 में तीसरा स्थान हासिल किया है।

चिकित्सा मंत्री ने किया ऑक्सीजन प्लांट व क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 4 फरवरी, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कूकस स्थित महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश ऑक्सीजन के मामले में पूर्णत: आत्मनिर्भर है। पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन के लिये 40 हजार कंसेंट्रेटर की व्यवस्था की जा चुकी है, जबकि 472 से अधिक प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं।
- उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना राज्य सरकार के लिये सहयोग का काम करेगी।
- महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इटली से आयातित ऑक्सीजन प्लांट की लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इस प्लांट की विशेषता है कि यह सामान्य ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सकता है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च

चर्चा में क्यों?

- 3 फरवरी, 2022 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने शासन सचिवालय स्थित निदेशालय में विभाग की वेबसाइट के अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से अपग्रेड होने वाली यह राज्य की पहली विभागीय वेबसाइट है।

- वेबसाइट को आकर्षक बनाने के साथ इसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं। वेबसाइट के मुख्य पेज पर कई जानकारी आसानी से मिल जाएंगी। प्रेस विज्ञप्तियाँ मुख्य पेज पर ही सामने आ जाएंगी।
- इन्हें विभाग, जिला एवं विशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी के अनुसार देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ राज्य सरकार की योजनाओं एवं पत्रकार कल्याण से जुड़ी योजनाओं को देख सकते हैं। मुख्य पेज पर ही लेटेस्ट ऑडियो, वीडियो, फोटो, पोस्टर एवं विज्ञापन सहित कई जानकारियाँ प्रदर्शित की गई हैं।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट के निर्माणकर्त्ता एवं मुख्यमंत्री कार्यालय आईटी सेल के प्रभारी राजेश सैनी ने बताया कि वेबसाइट को मुख्यमंत्री सूचना तंत्र से कनेक्ट किया गया है एवं डीआईपीआर के बजट घोषणा तथा जन-घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु सीएम डायरेक्शंस एवं उपलब्धियाँ भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई हैं।
- पोर्टल को समस्त जिलों की वेबसाइट से भी जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। अब डीआईपीआर के जनसंपर्क अधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति को जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जन कल्याण पोर्टल के मोबाइल ऐप पर भी राज्य स्तर एवं जिला स्तर की समस्त प्रेस रिलिज को भी देखा जा सकता है।
- जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से 33 जिलों की वेबसाइट बनाई गई है। 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' की वेबसाइट भी जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से बनाई गई है। डीआईपीआर पहला ऐसा विभाग है जिसकी वेबसाइट भी जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से बनाई गई है।

जयपुर के चौंप में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 5 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर के चौंप में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- जयपुर का यह स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा एवं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के बाद विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसकी दर्शक क्षमता 75 हज़ार होगी।
- इस स्टेडियम के निर्माण के लिये बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए अनुदान देगी।
- यह स्टेडियम 5 साल में लगभग 650 करोड़ की लागत से दो चरणों में बनेगा। पहले चरण में 40 हज़ार दर्शक क्षमता और दूसरे चरण में 35 हज़ार दर्शकों की बैठक क्षमता को विकसित किया जाएगा।
- राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनवाए जा रहे इस अत्याधुनिक स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, क्रिकेट अकादमी, हॉस्टल, जिम, रेस्टोरेंट के साथ ही कॉन्फ्रेंस हाल का निर्माण किया जाएगा।
- जयपुर में एसएमएस स्टेडियम, जोधपुर में बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम, उदयपुर में बन रहे स्टेडियम तथा जयपुर के पास चौंप में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चार स्टेडियम होंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 1931 में राजपूताना क्रिकेट संघ बना था। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में क्रिकेट संघ बने हुए हैं।

राजस्थान युवा पखवाड़ा

चर्चा में क्यों ?

- 7 फरवरी, 2022 को प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर शांति एवं अंहिसा निदेशालय, राजस्थान द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से 'राजस्थान युवा पखवाड़े'का शुभारंभ किया गया, जो 20 फरवरी, 2022 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- शांति और अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि युवा पखवाड़ा के अंतर्गत राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन राज्य के ज़िलास्तरीय अहिंसा प्रकोष्ठों का प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजित किये गए।
- राजस्थान युवा पखवाड़ा कार्यक्रम के समापन अवसर पर 20 फरवरी को शांति और अहिंसा निदेशालय की वेबसाइट का उद्घाटन एवं प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा।
- राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य सचिव ने बताया की प्रदेश के सभी ज़िला व उपखंड स्तर पर ज़िला युवा बोर्ड एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन व ज़िला अहिंसा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान युवा पखवाड़ा मनाया जाना है।
- नेहरू युवा केंद्र संगठन, राजस्थान भारत स्काउट व गाइड, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. के स्वयं सेवक, संबंधित ज़िले के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को आमंत्रित कर कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए युवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा।
- इस पखवाड़े के तहत आयोजित किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों में जनकल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्विज एवं प्रतियोगिता आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

लोकायुक्त ने राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रस्तुत किया 33वाँ समेकित प्रतिवेदन

चर्चा में क्यों ?

- 7 फरवरी, 2022 को राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी. के. लोहरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वाँ समेकित प्रतिवेदन (1 मार्च, 2018 से 31 दिसंबर, 2021 तक) प्रस्तुत किया।

प्रमुख बिंदु

- लोकायुक्त सचिवालय के उप सचिव हर्ष कुमार मिश्रा ने बताया कि लोकायुक्त लोहरा द्वारा 9 मार्च, 2021 को पदभार ग्रहण करने के समय कुल 9 हज़ार 810 शिकायतें लंबित थीं।
- कोविड महामारी के समय विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोहरा ने पीड़ित व्यक्तियों की परिवेदनाओं को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी अवकाश के दिसंबर 2021 तक कुल 5 हज़ार 43 शिकायतों का निस्तारण किया।
- उप सचिव ने बताया कि 1973 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के बाद से परिवेदनाओं का यह सबसे अधिक निस्तारण है।

गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 7 फरवरी, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शून्य से 2 वर्ष तक के बच्चों को नौ तरह की बीमारियों से बचाने के लिये जयपुर में 'गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 4.0' टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान में उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया है, जो नियमित टीकाकरण से किसी भी कारणवश वंचित रह गए हैं। अभियान के तहत ज़िले के करीब 487 बच्चों तथा 114 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान का प्रथम चरण आगामी 13 फरवरी तक संचालित होगा। अभियान का दूसरा चरण 7 मार्च से 13 मार्च तथा तीसरा चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा।
- इस अभियान के दौरान 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को नौ तरह की बीमारियों से बचाने के लिये बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, एफआईपीवी, आरवीवी, पीसीवी तथा एमआर के टीके लगाए जाएंगे। इसी प्रकार नियमित टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं को टीडी-1, टीडी-2 व बूस्टर टीडी के टीके लगाए जाएंगे।

- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम के ज़रिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 4.0 की शुरुआत की।
- गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तीन राउंड (दौर) होंगे और यह देश के 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 416 ज़िलों (आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिये चिह्नित 75 ज़िलों सहित) में संचालित किया जाएगा। इसके पहले राउंड (फरवरी-अप्रैल 2022) में 11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आईएमआई 4.0 को संचालित करेंगे। ये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं- असम, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा व छत्तीसगढ़।
- वहीं, अन्य 22 राज्य अप्रैल से मई 2022 तक राउंड संचालित करेंगे। इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पुदुच्चेरी, दिल्ली, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

प्रदेश के 1001 गाँवों में सभी परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सौगात

चर्चा में क्यों?

- 7 फरवरी, 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राजस्थान के 1001 गाँवों में सभी परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सुविधा मुहैया करा दी गई है। इन गाँवों में सभी लोगों को अपने घर पर ही नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य के 617 गाँवों में 90 प्रतिशत से अधिक, 705 गाँवों में 80 प्रतिशत से ज़्यादा तथा 772 गाँवों में 70 प्रतिशत से अधिक परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन के ज़रिये पेयजल आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में प्रतिदिन करीब 3 हज़ार नए ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिये जा रहे हैं।
- प्रदेश के ज़िलों में श्रीगंगानगर के सर्वाधिक 192 गाँवों में सभी परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन में कवर किया जा चुका है। नागौर के 161, राजसमंद के 92, चूरु के 81, जयपुर के 71, हनुमानगढ़ के 62, भीलवाड़ा के 40, सीकर के 39, जोधपुर के 34 एवं बीकानेर के 27 गाँवों में 'हर घर जल' कनेक्शन का कवरेज पूरा कर लिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जेजेएम के तहत अब तक 35 हज़ार 776 गाँवों में 128 बृहद् पेयजल परियोजनाओं और 9188 मल्टी एवं सिंगल विलेज परियोजनाओं सहित कुल 9316 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 86 लाख 21 हज़ार 450 'हर घर जल' कनेक्शन की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं।
- इसके विरुद्ध अब तक 25 हज़ार 937 गाँवों में 8673 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियाँ (62 लाख 51 हज़ार 516 'हर घर जल' कनेक्शन के लिये), 25 हज़ार 641 गाँवों में 8148 स्कीम्स (62 लाख 3 हज़ार 603 'हर घर जल' कनेक्शन के लिये) की निविदाएँ तथा 13 हज़ार 20 गाँवों में 5440 स्कीम्स में 32 लाख 29 हज़ार 482 'हर घर जल' कनेक्शन के लिये कार्यादेश जारी कर दिये गए हैं।

25 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिये एमओयू

चर्चा में क्यों?

- 8 फरवरी, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में राज्य के 25 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एमओयू हस्ताक्षर किये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्रेया गुहा तथा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से नंद घर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु झींगन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- इस एमओयू के तहत अनिल अग्रवाल फाउंडेशन करीब 750 करोड़ रुपए (प्रति आंगनबाड़ी 3 लाख रुपए) व्यय कर राज्य में 25 हज़ार नंद घर विकसित करेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे इन केंद्रो के बुनियादी ढाँचे में सुधार होने के साथ ही इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। इससे मातृ एवं शिशु मृत्युदर को और कम करने में भी मदद मिलेगी।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। इसी का परिणाम है कि अब करीब 95 प्रतिशत प्रसव संस्थागत होने लगे हैं।
- उल्लेखनीय है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने नि:शुल्क सेनेटरी नैपकीन वितरण के लिये 'उड़ान योजना' शुरू की है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई इस योजना के माध्यम से गाँव-ढाणी तक महिलाओं एवं किशोरियों को सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।
- महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि राज्य में करीब 62 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 6 तरह की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 13 ज़िलो में 1300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नंद घर के रूप में विकसित हो चुके हैं।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू

चर्चा में क्यों?

- 8 फरवरी, 2022 को राजस्थान राज्य सरकार तथा निवेशकों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख 5 हज़ार करोड़ के एमओयू एवं एलओआई पर हस्ताक्षर हुए तथा इनका आदान-प्रदान किया गया। इस निवेश से प्रदेश में करीब 90 हज़ार मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के 5 सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ 3 लाख 5 हज़ार करोड़ रुपए के 90 गीगावाट से अधिक क्षमता के एमओयू एवं एलओआई हस्ताक्षरित किये गए।
- इनमें एनटीपीसी की ओर से 40 हज़ार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, एनएचपीसी की ओर से 20 हज़ार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, सतलज जल विद्युत निगम की ओर से 50 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 10 गीगावाट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से 40 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 10 गीगावाट तथा एसईसीआई की ओर से 9 हज़ार करोड़ की लागत से 2 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू एवं एलओआई शामिल हैं।
- इसी प्रकार रिलायंस समूह की ओर से 1 लाख करोड़ की लागत से 20 गीगावाट, एक्सिस एनर्जी समूह की ओर से 37 हज़ार करोड़ की लागत से 28 गीगावाट सोलर पार्क, सोलर प्रोजेक्ट एवं 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्यूफैक्चरिंग एवं सुखवीर एग्रो समूह की ओर से 2 गीगावाट एवं 100 मेगावाट क्षमता (बॉयोमास) के अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू एवं एलओआई शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाने के लिये सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति-2019 तथा विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जारी की थी। निवेशकों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिये रिप्स-2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, एमएसएमई एक्ट जैसे नीतिगत निर्णय लिये गए।

नोट :

- इस अवसर पर एनएचपीसी के निदेशक वाईके चौबे ने कहा कि एनएचपीसी राजस्थान में 50 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम कर रहा है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एनएचपीसी 10 हज़ार मेगावाट क्षमता उत्पादन के लिये 20 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता संवर्द्धन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में एमओयू

चर्चा में क्यों ?

- 10 फरवरी, 2022 को राजस्थान जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉ. महेश जोशी की उपस्थिति में शासन सचिवालय में अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता संवर्द्धन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू पर अटल भूजल योजना की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) तथा भूजल विभाग की ओर से परियोजना निदेशक सूरजभान सिंह एवं आईएमटीआई, कोटा की तरफ से महानिदेशक राजेंद्र पारीक ने हस्ताक्षर किये।
- इस एमओयू के तहत आईएमटीआई, कोटा द्वारा राजस्थान में राज्य, ज़िला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2021-22 में 56 तथा वर्ष 2022-23 में 336 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिन पर करीब 1.63 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
- सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (इरिगेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट-आईएमटीआई), कोटा द्वारा चालू एवं अगले वित्तीय वर्ष में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि अटल भूजल योजना प्रदेश के 17 ज़िलों के 38 पंचायत समिति क्षेत्रों में लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्रियान्वित की जा रही है। इससे करीब 1.55 लाख कृषकों को लाभ होगा।
- इस योजना में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने एवं इसके न्यायसंगत उपयोग के लिये कृषि, उद्यानिकी, जलग्रहण एवं भूसंरक्षण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वन, ऊर्जा तथा भूजल विभाग की योजनाओं द्वारा भूजल क्षेत्रों में कुशलतम जल प्रबंधन को प्रमोट करने एवं गिरते भूजल स्तर की रोकथाम का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है।
- अटल भूजल योजना में सीधे जो दो घटक शामिल किये गए हैं, उनमें पहला संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता संवर्धन द्वारा टिकाऊ भूजल प्रबंधन तथा दूसरा केंद्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के साथ-साथ नवाचारों को बढ़ावा देते हुए सामुदायिक सहभागिता से टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है। इनमें से प्रथम घटक के अंतर्गत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये ये प्रशिक्षण आयोजित होंगे।

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

- 10 फरवरी, 2022 को राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने विधानसभा में कहा कि बूंदी ज़िले में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाईगर रिज़र्व बनाए जाने की केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई, 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
- एनटीसीए द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व के क्रिटिकल टाइगर हैबीटैट (कोर) एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु धारा 38 वी (4) के अनुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

नोट :

- इस समिति द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व, ज़िला बूंदी के कोर (सी.टी.एच.) तथा बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु 24 जनवरी, 2022 को राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिये एक बफर की तरह काम करता है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। यह लगभग 252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है।
- राजस्थान सरकार ने इसे 20 मई, 1982 को राजस्थान वन्य प्राणी और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 की धारा 5 के अंतर्गत अभयारण्य घोषित किया था।
- रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति और विभिन्न जीवों, जैसे- भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सुस्त भालू, गोल्डन जैकल, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को देखा जा सकता है।

सघन मिषन इंद्रधनुष 4.0 अभियान

चर्चा में क्यों?

- 11 फरवरी, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान का आरंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में जयपुर ज़िले के करीब 487 बच्चों और 114 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- इन बच्चों को नौ तरह की बीमारियों से बचाने के लिये बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइट्स बी, पेंटावेलेंट, एफआईपीवी, आरवीवी, पीसीवी तथा एमआर के टीके लगाए जा रहे हैं।
- इस अभियान के अंतर्गत उन बच्चों को शामिल किया गया है, जो नियमित टीकाकरण से किसी भी कारणवश वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार नियमित टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं को टीडी-1, टीडी-2 व बूस्टर टीडी के टीके लगाए जा रहे हैं।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान 209 सत्रों में आयोजित किया जा रहा है।
- इसका प्रथम चरण 13 फरवरी, 2022 तक संचालित होगा। इसके बाद अभियान का दूसरा चरण 7 मार्च से 13 मार्च, 2022 तक, तीसरा चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2022 तक संचालित किया जाएगा।

62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- 13 फरवरी, 2022 को राजस्थान की कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी डी कल्ला के मुख्य आतिथ्य में झालाना स्थित राजस्थान ललित कला अकादमी परिसर में 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मंत्री द्वारा 10 कलाकारों को श्रेष्ठ कृतियों के लिये पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 584 कलाकृतियों का अवलोकन करने के पश्चात् विभाग द्वारा इन 10 सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का चयन किया गया था। इन कलाकारों को ट्रॉफी, स्मृतिचिह्न के साथ-साथ 25 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
- ज्ञातव्य है कि 16 नवंबर, 2021 को राजस्थान ललित कला अकादमी के निर्णायक मंडल द्वारा 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के लिये राज्य कला पुरस्कारों की घोषणा की गई।

नोट :

- प्रदर्शनी में जिन दस कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कृत किया गया है, वे इस प्रकार हैं-
    - रिचा माहेश्वरी (कोसमोस)
    - कमल किशोर जोशी (मेघराज)
    - डॉ. मणि भारतीय (लैंडस्केप)
    - योगेंद्र सिंह नरूका (ए मैरिज पार्टी)
    - दुर्गेश कुमार अटल (प्लोवर)
    - निर्मल यादव (द ल्यूनार शेड्स)
    - कुमुदनी भरावा सोनी (कहाँ घूमें कहाँ जाएँ)
    - राजेंद्र प्रसाद मीना (मूवमेंट आफ जॉय)
    - सुनील कुमावत (होप-3)
    - ऋतु शेखावत (फ्लोइंग वर्लपुल)
- राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान की ललित कला संस्कृति को बढ़ावा देने, फैलाने और विकसित करने के लिये राजस्थान सरकार का प्रमुख ललित कला संस्थान है। यह एक गैर-लाभकारी, स्वायत्त निकाय है, जिसे कला और संस्कृति मंत्रालय, राजस्थान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- कला एवं संस्कृति विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के कलाकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना तथा उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है।
- मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने कहा कि कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में राज्य का प्रत्येक क्षेत्र अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। भविष्य में सभी कलाकारों को एनएफटी टोकन देने का प्रावधान किया जाएगा ताकि यदि उनकी कलाकृति कहीं भी बिके तो उसके मूल्य का एक हिस्सा कलाकार तक आवश्यक रूप से पहुँचे।

हल्दीघाटी युद्ध

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को लेकर पुन: विवाद खड़ा हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इतिहास के विषय में पढ़ाया जा रहा है कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की जीत हुई थी जबकि अनेक इतिहासकार इसके खिलाफ हैं। उनके अनुसार साक्ष्य यह साबित कर चुके हैं कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी।
- इस विवाद के पश्चात् विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रो. दिग्विजय भटनागर ने अपनी पुस्तक 'राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा' के संदर्भ में हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की जीत के बारे में लिखे जाने को लेकर स्पष्ट किया है कि यह पुस्तक इतिहासकारों की पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों पर आधारित है, जिसका उन्होंने केवल संपादन किया है। ऐसे में जल्द ही संशोधन के साथ नई पुस्तक आएगी जिसमें हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था।
- अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था।

मरु महोत्सव 2022 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 13 फरवरी, 2022 को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उप निवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री शाले मोहम्मद एवं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने गोल्डन बैलून आसमान में उड़ाकर चार दिवसीय मरु महोत्सव का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन विभाग ने इस बार मरु महोत्सव को 'उम्मीदों की उड़ान' का नाम दिया है।
- सालमसागर तालाब की पाल पर आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री शाले मोहम्मद ने झंडी दिखाकर भव्य शोभायात्रा का भी शुभारंभ किया।
- शोभायात्रा में सजे-धजे ऊँटों पर सवार बीएसएफ के जांबाजों, बीएसएफ महिला टुकड़ी, बालिकाओं एवं महिलाओं की मंगल कलश यात्रा और विभिन्न झांकियाँ आकर्षण का केंद्र रहीं।
- रास्ते भर कलाकारों के समूहों ने कालबेलिया, अश्व, कच्छी घोड़ी, गैर आदि लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया।
- इस कल्चर महोत्सव में सेलिब्रिटीज नाईट, पोखरण खुहडी और सम के रेतीले टीलों पर कार्यक्रमों के साथ-साथ मरुश्री, मिस मूमल, मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांध, मूमल महिंद्रा, ऊँट श्रृंगार और शान-ए-मरुधरा, पणिहारी मटका रेस प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाएंगी।
- मरु महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में मिस्टर एवं मिस पोखरण प्रतियोगिता हुई। इसमें निकिता राठौड़ ने मिस पोखरण एवं भरत बोहरा ने मिस्टर पोखरण का खिताब जीता। इन प्रतिभागियों में कन्या कॉलेज पोखरण की खुशी गौड़ ने दिव्यांग होते हुए भी प्रतियोगिता में भाग लिया।
- मुख्य कार्यक्रम की साफा बांधो प्रतियोगिता में दुर्जनसिंह भाटी विजेता रहे। रस्सा कसी में टीम कपिल विजेता रही। मल्लश्री का खिताब विक्रम जोशी ने अपने नाम किया तथा मटका दौड़ में रूकड़ी ने जीत हासिल की।
- इसके साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता में तनीषा खत्री, मांडना में जसोदा एवं रंगोली प्रतियोगिता में खुशबू विजेता रहीं। प्हले दिन के कार्यक्रम का समापन पद्मश्री अनवर खाँ एवं लंगा पार्टी के कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ।
- विजेताओं को अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद एवं आरसीए अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत तथा अन्य अतिथियों ने पुरस्कृत किया।
- मुख्य समारोह परिसर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें बीएसएफ द्वारा देश की प्रथम पंक्ति पर सुरक्षा में लगे सैनिकों को मुहैया करवाए जाने वाले हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ 7.66 एमएम गन, असाल्ट रायफल, एक्स-95, इंसास, एलएमजी, 84 एमएम जीआरएल, बैरिस्टा, सहित अन्य हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पोखरण विकास संस्थान, उरमूल, ऊँटनी के दूध, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हस्तशिल्प आदि से संबंधित प्रदर्शनियाँ लगाई गईं।
- उल्लेखनीय है कि 7 फरवरी, 1979 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने मरु महोत्सव का शुभारंभ किया था।

जोधपुर के शुभम राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बंगलुरू में आयोजित आईपीएल 2022 के 15वें सीजन की मेगा ऑक्शन में जोधपुर के शुभम गढ़वाल को राजस्थान रॉयल्स टीम ने बेस प्राइज 20 लाख रुपए में खरीद लिया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि शुभम गढ़वाल जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं।
- शुभम साउथ अफ्रीका में क्लब क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वे राजस्थान की रणजी टीम के भी सदस्य रहे हैं।
- पाँच माह पूर्व जयपुर में आयोजित कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता में शुभम गढ़वाल ने 12 बॉल में 50 रन बनाए थे। साथ ही क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था।

नोट :

सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण

चर्चा में क्यों?

- 14 फरवरी, 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आरक्षण देने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस मदन गोपाल व्यास और जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि जिसमें कहा गया कि नौकरी में आरक्षण देना या कितना देना राज्य का विशेषाधिकार है।
- हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिये राज्य सरकार की नौकरियों में कोटा तय करने का निर्देश दिया। साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियाओं को चार माह में पूरा करने को कहा।
- उच्च न्यायालय ने पुलिस उप-निरीक्षक बनने की इच्छा रखने वाले और इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य की याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया।
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के मामले में अपने फैसले में सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर फैसला दिया है।
- गौरतलब है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिये कर्नाटक सरकार ने सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है।
- ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है, जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है, तब महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है।
- वर्ष 2019 में संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित किया था।

राजस्थान के 6 बुनकर 'बुनकर पुरस्कार' के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

- 15 फरवरी, 2022 को उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त महेंद्र कुमार पारख की अध्यक्षता में उद्योग भवन में आयोजित हुई राजस्थान राज्यस्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक में प्रदेश के 6 बुनकरों का बुनकर पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत करने हेतु चयन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यस्तर पर चयनित पहले तीन बुनकरों को क्रमशः 21000, 11000 व 7100 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी तथा ज़िलास्तर पर चयनित तीन बुनकरों को क्रमशः 5100, 3100 व 2100 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि बुनकर पुरस्कार योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसके अंतर्गत राज्य में बुनकरों को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के 19 बुनकर बहुल ज़िलों में बुनकरों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत करने हेतु 3 लाख रुपए की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। विभाग को प्राप्त 32 प्रविष्टियों के अवलोकन उपरांत 6 प्रविष्टियों का नगद पुरस्कार हेतु चयन किया गया।
- इंद्रो (पोखरण, जैसलमेर) पोखरण पट्टू के लिये प्रथम स्थान पर रहीं, जबकि गुलाम अहमद (सवाई माधोपुर) ने प्लेन खेस के लिये द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं शक्ति सिंह नरूका (सिराही, टोंक) सूती साड़ी के लिये तृतीय स्थान पर रहे।
- वहीं मकबूल अहमद (मंगरोल, बारां) को कोटा डोरिया बैंगनी बूटी साड़ी, जबकि बुधराम (कांकनी, जोधपुर) को सूती दरी तथा सुमन (अमरपुरा बास, बीकानेर) का कोटिंग ऊनी के लिये सांत्वना पुरस्कार हेतु चयन किया गया।

नोट :

बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये रणनीति पत्र राज्य सरकार से स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

- 15 फरवरी, 2022 को राजस्थान के वन मंत्री हेमा राम चौधरी ने विधानसभा में बताया कि बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये एक रणनीति पत्र राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुका है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- वन मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020 में मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिज़र्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जाँच की गई है। प्राप्त जाँच रिपार्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये दिये गए सुझावों का परीक्षण एक टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है।
- वन मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक सतीश पूनियां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि रणथंभौर टाईगर रिज़र्व वन क्षेत्र में बाघों के लापता होने व गुमशुदगी, अवैध शिकार एवं क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौत होने के प्रकरणों में जाँच भारत सरकार द्वारा 13 मार्च, 2020 को गठित समिति द्वारा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।
- रणथंभौर टाईगर रिज़र्व की वर्ष 1973 में स्थापना के बाद वर्तमान में बाघों की संख्या अधिकतम है। रणथंभौर टाईगर रिज़र्व व समीपस्थ क्षेत्रों में बाघों एवं उनके शावकों की संख्या वर्ष 2019 में 66, वर्ष 2020 में 68 व वर्ष 2021 में 81 हो गई है।
- वर्तमान में नर एवं मादा बाघ का अनुपात भी 1:1.3 है, जो असामान्य है। 32 मादा बाघिनों में से अधिकांश प्रजनन आयु में हैं, जिसके कारण नए शावकों के जन्म में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच 44 शावकों का जन्म हुआ है।
- सरिस्का टाईगर रिज़र्व में वर्तमान में 25 बाघ हैं। वर्ष 2019 में 16 बाघ, 2020 में 23 बाघ व 2021 में 25 बाघ रहे। वर्तमान में नर एवं मादा बाघ का अनुपात यहाँ भी 1:1.22 है, जो असामान्य है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच 9 शावकों का जन्म हुआ है।
- मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिज़र्व में वर्तमान में 1 बाघिन है। वर्ष 2019 में 4 बाघ, 2020 में 1 बाघ व 2021 में 1 बाघ रहे। इस अंतराल में यहाँ 2 बाघ व 1 बाघिन की मृत्यु हुई और 2019 से 2021 के बीच 3 शावकों का जन्म हुआ है।
- रणथंभौर टाईगर रिज़र्व में वर्ष 2006 से 2014 तक भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा किये गए 1 शोध में यह उल्लेख किया गया कि रणथंभौर टाईगर रिज़र्व के रणथंभौर नेशनल पार्क एवं सवाई मानसिंह अभयारण्य क्षेत्र में टाईगर घनत्व केरिंग केपेसिटी के बराबर पहुँच चुका है।
- शोध के समय रणथंभौर टाईगर रिज़र्व प्रथम के क्षेत्र में 43 वयस्क बाघ थे, जबकि वर्तमान में बढ़कर 23 नर एवं 30 मादा सहित कुल 53 वयस्क बाघ हो गए हैं।

आरपीएससी एवं विभिन्न बोर्ड के अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण किया

चर्चा में क्यों ?

- 16 फरवरी, 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) एवं राजस्थान के विभिन्न बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों ने पदभार ग्रहण किये।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नवनियुक्त संजय कुमार श्रोत्रिय ने कार्यभार ग्रहण किया।
- कार्यभार ग्रहण करने के बाद संजय कुमार श्रोत्रिय ने कहा कि परीक्षाओं व साक्षात्कारों का समयबद्ध आयोजन उनकी प्राथमिकता रहेगा। आयोग की प्रक्रियाओं तथा कठिनाइयों के संबंध में वर्तमान सदस्यों व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आगामी कार्ययोजना निर्धारित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर, 1949 को हुई थी। आरंभिक चरण में आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस. के. घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
- राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में अनिल शर्मा ने अंबेडकर भवन में पदभार ग्रहण किया।

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उत्थान एवं कल्याण के लिये प्रभावी नीति का निर्धारण करने के लिये इस बोर्ड के गठन की घोषणा की थी।
- राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के नव मनोनीत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भी बोर्ड का पदभार ग्रहण किया तथा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर बोर्ड की पशुधन विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली।
- इस दौरान राजेंद्र सिंह सोलंकी ने सभी अधिकारियों से पशुधन के समग्र विकास के लिये समुचित सहयोग करने का आवह्वान करते हुए कहा कि पशुधन विकास की विभिन्न योजनाओं एवं उनके लाभ संबंधित जानकारियाँ राज्य के प्रत्येक किसान व पशुपालक तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता होगी।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के नव मनोनीत उपाध्यक्ष चुन्नीलाल राजपुरोहित ने भी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है।
- पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने भी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष पद पर रामसहाय बाजिया ने भी पदभार ग्रहण किया।

प्रदेश के कारागृहों में कॉनफैड द्वारा 'बंदी कैंटीन' की होगी शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 16 फरवरी, 2022 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्रीय कारागार जयपुर में कॉनफैड द्वारा बंदियों के लिये संचालित की जाने वाली बंदी कैन्टीन के उद्घाटन के साथ सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, दौसा एवं कोटपूतली में भी बंदी कैंटीन का वर्चुअल उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उदयलाल आंजना ने कहा कि सहकारिता एवं जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों के लिये बंदी कैंटीन की शुरुआत से बंदियों के लिये खाद्य सामग्री, कन्फैक्शनरी, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट्री के अतिरिक्त नोटबुक, पेंसिल एवं दैनिक उपयोग में आने वाली लगभग 43 से 58 प्रकार की सामग्री उपलब्ध होगी।
- कैंटीन की शुरुआत से ही पारदर्शिता के साथ बंदियों के लिये सही सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी तथा 6 माह उपरांत इसकी समीक्षा की जाएगी और सुझाव भी आमंत्रित किये जाएंगे ताकि कैदियों को कैंटीन के माध्यम से और बेहतर सुविधाएँ दी जा सकें। इस मॉडल को राज्य के सभी कारागृहों में शुरू किया जाएगा।
- प्रबंध निदेशक कॉनफैड वी.के. वर्मा ने बताया कि बंदी कैंटीन में जेल में बने वार्ड के अनुसार निर्धारित दिन को बंदी बॉयोमैट्रिक सत्यापन से अपना सामान क्रय कर सकेगा।
- इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने बंदियों की मांग पर कैन्टीन से प्रतिमाह दो हज़ार पाँच सौ रुपए की सीमा तक क्रय की जाने वाली सामग्री की सीमा को तीन हज़ार पाँच सौ रुपए बढ़ाने की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य की 140 जेलों में लगभग 23 हज़ार बंदी हैं।

मुख्यमंत्री ने किया 'राजस्थान स्वायत्त शासन' पत्रिका का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 17 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था की पत्रिका 'राजस्थान स्वायत्त शासन' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने पत्रिका के प्रकाशन के लिये संस्था के अध्यक्ष केवल चंद गुलेच्छा सहित अन्य पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के साथ ही अन्य विभागों के लिये भी यह पत्रिका संदर्भ पुस्तिका के रूप में उपयोगी साबित होगी।

नोट :

- इस पुस्तक से स्वायत्तशासी संस्थाओं से जुड़े कार्यों के संबंध में आमजन को आवश्यक जानकारियाँ मिल सकेंगी।
- संस्था के सचिव पूर्व आईएएस प्रदीप बोरड़ ने बताया कि पत्रिका में स्वायत्तशासी संस्थाओं से संबंधित आदेश, निर्देश, परिपत्रों के साथ ही अन्य उपयोगी जानकारियों का समावेश किया गया है।

एनएचएम और विश फाउंडेशन के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों ?

- 18 फरवरी, 2022 को राजस्थान के राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से एनएचएम राजस्थान एवं तकनीकी पार्टनर संस्थान 'विश'फाउंडेशन के बीच स्वास्थ्य भवन में एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीना ने बताया कि तीन साल की अवधि वाले इस एमओयू के होने से प्रदेश के 100 स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और संसाधनों के समुचित उपयोग में आवश्यक सुधार लाए जाएंगे।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों में शामिल मापदंडों के अनुसार राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुविधाओं में और अधिक सुधार लाकर आमजन को सुलभ चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न स्तरों पर कुशल मॉनीटर्स द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। मॉनीटरिंग के अनुसार प्रत्येक सेवा के लिये अंक दिये जाते हैं, जिनके आधार पर विजेता स्वास्थ्य संस्थानों को तीनवर्षीय प्रमाण-पत्र तथा प्रोत्साहनस्वरूप वित्तीय राशि प्रदान की जाती है।
- राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर की उपस्थिति में मिशन निदेशक एनएचएम एवं संयुक्त सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने तथा विश फाउंडेशन की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश रंजन सिंह ने हस्ताक्षर किये।

'ऑपरेशन अस्मिता'

चर्चा में क्यों ?

- 19 फरवरी, 2022 को मुख्य सचिव के समक्ष बूंदी ज़िला कलेक्टर रेणु जयपाल ने 'ऑपरेशन अस्मिता' नवाचार का प्रेज़ेंटेशन दिया।

प्रमुख बिंदु

- बूंदी ज़िले के कुछ क्षेत्रों में देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिये ज़िला प्रशासन द्वारा 'ऑपरेशन अस्मिता' को शुरू किया जा रहा है।
- इस नवाचार के ज़रिये नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की टीम एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न विकासोन्मुखी गतिविधियों द्वारा शिक्षा और रोज़गार से जोड़कर पीड़ित वर्ग को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
- ज़िला कलेक्टर ने बताया कि 'ऑपरेशन अस्मिता' बूंदी ज़िले के एक समुदाय विशेष के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है।
- ज़िले के गाँव रामनगर से इसकी शुरुआत की जा रही है। हिंडोली के शंकरपुरा तथा इंद्रगढ़ के मोहनपुरा को भी शामिल किया जाएगा।
- 'ऑपरेशन अस्मिता' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये चरणवार कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से गतिविधियाँ की जाएंगी।
- चयनित गाँवों में चिह्नित परिवारों के लक्षित समूह के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्य होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्ता कैलाश सत्यार्थी (बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता) के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियाँ होंगी।
- शिक्षा से वंचित या ड्रॉपआउट के लिये उनके अनुकूल शैक्षणिक सुविधाएँ दी जाएंगी। शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार से जोड़ा जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काउंसिलिंग, जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से ब्रेन वाशिंग कर स्वास्थ्य एवं करियर निर्माण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा।

- परिवार की आजीविका के दृष्टिगत संबंधित विभागों के सहयोग से कौशल विकास एवं रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाए जाएंगे।
- समय-समय पर विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित गाँवों के लिये प्लेसमेंट शिविर आयोजित करवाए जाएंगे और शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार के अवसर दिये जाएंगे।
- खेल प्रतिभाओं को अवसर देने के लिये संबंधित क्षेत्रों में खेल मैदानों का विकास किया जाएगा तथा खेल सुविधाएँ एवं आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएंगी।
- इस नवाचार के क्रियान्वयन में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की टीम के साथ बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन अन्य अनुभवी विशेषज्ञ संस्थाओं एवं व्यक्तियों की मदद ली जाएगी। ज़िला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं का भी सहयोग रहेगा।

'मेड इन इंडिया' पुस्तक

चर्चा में क्यों?

- 19 फरवरी, 2022 को भारतीय रेलवे लेखा सेवा की अधिकारी तारिका रॉय और भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी सौम्या गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक 'Mad(e) in India' पर आईएएस लिटरेरी सोसायटी राजस्थान द्वारा वर्चुअल इंटरेक्शन सेशन के माध्यम से चर्चा की गई। तारिका रॉय और सौम्या गुप्ता की यह पहली किताब है।

प्रमुख बिंदु

- तारिका रॉय ने अपनी किताब पर चर्चा करते हुए बताया कि यह पुस्तक हमारे देश भारत और भारतीयों की आदतों, रहन-सहन, आचारख्रव्यवहार तथा यहाँ की संस्कृति एवं परंपराओं के मजेदार पहलुओं की खोज है।
- इस किताब से हर भारतीय खुद को जोड़ सकता है। यह पुस्तक बताती है कि हम एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं, हमारी विचित्रता, अंधविश्वास, असंख्य देवी-देवता और पवित्र पुरुष, हमारे भीड़ख्रभाड़ वाले शहर और सड़कें, फिल्मी सितारों और फिल्मी शैली के साथ हमारा जुनून, बड़ी और छोटी सभी समस्याओं को हल करने के हमारे जुगाड़ू तरीके, हमारे विविध व्यंजन, सांस्कृतिक परंपराएँ और कला रूप तथा विविधता में एकता, जो हमारे सतही मतभेदों को पाटती है।
- इस पुस्तक का एक अध्याय भारतीय रेल से संबंधित विभिन्न पहलुओं से जुड़ा है, जो पाठकों की बहुत-सी यादें ताजा कर देगा।
- सौम्या गुप्ता ने बताया कि यह किताब हमारे देश से बाहर रहने वाले लोगों को भी रोचक, अनूठे और विशिष्ट भारत की तस्वीर दिखाएगी। इस किताब में पाठकों को ट्रकों के पीछे लिखी इबारतों से लेकर लोगों के मुँह पर रहने वाले तकिया कलामों के मजेदार रूप पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही पैरेंटल कंट्रोल और हाईवे स्पेशल ढाबों की दुनिया के मज़ेदार किस्से भी। इस पुस्तक में देश की विशेषताओं और अनोखेपन को एक नए तरीके से पाठक के सामने रखने का प्रयास किया गया है।

विधानसभा का आईओएस मोबाइल ऐप लॉन्च

चर्चा में क्यों?

- 22 फरवरी, 2022 को राजस्थान विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने विधानसभा में विधानसभा का आईओएस (आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम) आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा के सचिव ने बताया कि इस नवीनतम तकनीक में अग्रणी राजस्थान विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित इस ऐप में विधानसभा के कार्य से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध रहेगी।
- इस ऐप में प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक, कार्यसूची, सत्र समीक्षा, बजट भाषण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, सदन की कार्यवाही के विवरण सहित विधानसभा के सदस्यों के उपयोग हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली व समाचार कतरनें भी उपलब्ध रहेंगी। इस ऐप में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन परिचय भी उपलब्ध होंगे।
- उल्लेखनीय है कि विधानसभा का एंड्राइड आधारित मोबाइल ऐप पूर्व में संचालित है। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण धारक उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा के लिये यह ऐप जारी किया गया है।

राजस्थान बजट वर्ष 2022-23

चर्चा में क्यों ?

- 23 फरवरी, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट वर्ष 2022-23 विधानसभा में पेश किया।

प्रमुख बिंदु

वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के प्रमुख बिंदु निम्न हैं-

- वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 2 लाख 14 हज़ार 977 करोड़ 23 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ हैं।
- वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 2 लाख 38 हज़ार 465 करोड़ 79 लाख रुपए का राजस्व व्यय है।
- वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 23 हज़ार 488 करोड़ 56 लाख रुपए है।
- वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 58 हज़ार 211 करोड़ 55 लाख रुपए है जो GSDP का 4.36 प्रतिशत है।

राजस्थान बजट वर्ष 2022-23 के अन्य प्रमुख बिंदु हैं-

- शहरी क्षेत्र में रोज़गार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा।
- समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग करने पर 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क।
- 'चिरंजीवी योजना' में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया।
- 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना' लागू करने की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक दुर्घटना कवर रहेगा।
- रोड सेफ्टी अधिनियम लाया जाएगा और राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर में State Road Safety Institute की स्थापना की जाएगी।
- कृषि बजट के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में समेकित निधि, राज्य की स्वायत्तशाषी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 78 हज़ार 938 करोड़ 68 लाख रुपए का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है।
- कृषि बजट के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 हज़ार करोड़ रुपए की। इस योजना के अंतर्गत 11 मिशन हैं।

राज्य बजट 2022-23 में पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

- 23 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किये गए राज्य बजट 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा और संबल प्रदान करने के लिये पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य बजट 2022-23 में प्रदेश वासियों की जरूरतों को पूरा करने और प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये कई घोषणाएँ की गई हैं। सभी घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक प्रावधान भी किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार कृषि बजट पेश किया गया है।
- राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला करते हुए 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिये पहले की तरह पुरानी पेंशन की घोषणा की गई है।
- पर्यटन संबधी कार्यों को गति देने के लिये पर्यटन विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए किया गया है। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

नोट :

- बजट में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 'साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना', पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत आनलाइन बुकिंग पोर्टल और मोबाइल एप सहित पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा के लिये 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती करने का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन मंत्री ने कहा कि डूँगरपुर व बाँसवाड़ा क्षेत्र और वहाँ के आस-पास के धार्मिक स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'वागड़ टूरिस्ट सर्किट'को विकसित किया जाएगा, साथ ही गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा में 10 करोड़ रुपए की लागत से वैदिक गुरुकुल बनाया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों को दिये जाने वाले मानदेय व अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। इससे कलाकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा।

'उदय खेल महोत्सव' का समापन

चर्चा में क्यों?

- 26 फरवरी, 2022 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के निंबाहेड़ा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने एवं खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के मकसद से शुरू किये गए सात दिवसीय 'उदय खेल महोत्सव'का समापन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- 'उदय खेल महोत्सव'के दौरान विभिन्न खेल वर्ग में प्रतियोगिताएँ आयोजित हुईं जिनमें खिलाड़ियों ने काफी उत्साह दिखाया।
- फुटबॉल में फाइनल मैच अमन क्लब और उदय क्लब के बीच हुआ जिसमें अमन क्लब निंबाहेड़ा की टीम विजेता रही। वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता में मांगरोल क्लब और गागरोन क्लब के बीच अंतिम मैच हुआ जिसमें मांगरोल की टीम विजेता रही।
- वॉलीबॉल में अरनोदा क्लब और मरजीवी क्लब के बीच मैच हुआ जिसमें मरजीवी क्लब की टीम विजेता रही। इसी प्रकार से कबड्डी में फाचर अहिरान और कदमाली के बीच मैच हुआ।
- विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और टीमों को प्रोत्साहन राशि 55,555 रुपए प्रदान की गई तथा संबंधित विजेता टीम को अपने वार्ड में विकास कार्य के लिये 10 लाख रुपए की राशि का चेक वितरण किया गया। उप-विजेता टीमों को 25,555 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई।
- सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। उदय खेल महोत्सव से खिलाड़ियों के शारीरिक-मानसिक विकास के साथ भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। एक-दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान होता है।
- खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपने भाषण में खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया एवं खेल के विकास के लिये निंबाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिये दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

नोट :